



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 267 राँची, मंगलवार, 17 वैशाख, 1946 (श०)
7 मई, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
3 मई, 2024

सं०-14/न्याय-02/2022-2760-- विभागीय अधिसूचना सं०-6471, दिनांक-23.10.2010 के द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :-

(क) श्री द्वारिका प्रसाद सिंह, रा०पु०से०, पुलिस उपाधीक्षक अपने वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करेंगे।

(ख) श्री सिंह भविष्य में किसी स्वतंत्र प्रभार के पद पर पदस्थापित नहीं किये जायेंगे।

2. तदुपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-720, दिनांक-05.02.2019 द्वारा उक्त दण्ड को निम्नरूपेण परिमार्जित किया गया है:-

(क) सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 88 (1) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-1698, दिनांक 18.02.2012 में दिये गये नियम के आलोक में श्री सिंह को पुलिस उपाधीक्षक के वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करने के दण्ड को 02 वर्षों तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया तथा सजा समाप्ति के पश्चात सेवा संहिता के नियम-85 के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि, जिस प्रक्रम पर वह अधिसूचना निर्गत की तिथि को कार्यरत थे, उस आधार पर अनुमान्य किया गया।

(ख) W.P.(S) No-620/2010 एवं W.P. (S) No-6254/2010 द्वारिका प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश के आलोक में उक्त द्वितीय दण्ड को निरस्त किया गया।

3. तदुपरांत श्री द्वारिका प्रसाद सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर **LPA No-596/2017** में **दिनांक-07.06.2022** को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण दायर अवमाननावाद (सिविल) सं०-346/2023, दिनांक-04.01.2024 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

"..... the order of punishment dated 1st Nov.2010 modified to the extent that the punishment of revision to original pay scale was modified to **stoppage of two increment for one year.....**"

उल्लेखनीय है कि संगत मामले में राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर **SLP. No-19008/2023** को **दिनांक-28.08.2023** को खारिज किया जा चुका है।

4. अतः उक्त अवमाननावाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में श्री द्वारिका प्रसाद सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक को विभागीय अधिसूचना सं०-6471, दिनांक-23.10.2010 द्वारा दिये दंड '**अपने वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम पर वेतन प्राप्त करेंगे**' को 'एक वर्ष के लिए दो वेतन वृद्धि रोकने' के दंड के रूप में संशोधित किया जाता है।

5. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव।
